राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध II जमानत आवेदन संख्या 1197/2024

बुधाराम पुत्र श्री पेमाराम, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी बावरियों का वास कांकाणी, थाना लूनी, जिला जोधपुर।
(जिला जेल, चित्तौड़गढ़ में बंद)

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री भंवर सिंह राठौड़
प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री मुख्तियार खान, पीपी
श्री राम तुमेर सी.आई.
पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेड़ा,
जिला चित्तौड़गढ़

माननीय श्री न्यायमूर्ति दिनेश मेहता

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य **20/02/2024**

1. जमानत के लिए यह दूसरा आवेदन आवेदक द्वारा सीआरपीसी की धारा 439 के तहत अपराध के लिए पुलिस स्टेशन निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (इसके बाद 'एनडीपीएस अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 8 और 15 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 100/2023 के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक की ओर से दायर की गई पहली जमानत अर्जी (एस.बी. आपराधिक विविध जमानत अर्जी संख्या 15616/2023) को 18.12.2023 को वापस ले लिया गया, आरोप पत्र दाखिल होने के बाद नए सिरे से दाखिल करने की छूट के साथ खारिज कर दिया गया।

3. आवेदक के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/15, 25 और 29 के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए आरोप पत्र दायर किया गया है।

4. आवेदक के विद्वान वकील श्री भंवर सिंह ने संक्षेप में दो तर्क उठाए हैं। सबसे पहले तो यह कि लादू राम नाम के व्यक्ति ने फर्जी तरीके से दस्तावेजों पर वर्तमान आवेदक के हस्ताक्षर करवा लिये और वाहन का पंजीयन आवेदक के नाम पर करा लिया। इसलिए, आवेदक को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/25 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह कानून की नजर में वाहन का मालिक नहीं है।

5. दूसरे, जांच अधिकारी ने कॉल डिटेल के रूप में या अन्यथा कोई सबूत एकत्र नहीं किया है जिससे यह स्थापित हो सके कि विचाराधीन ट्रक का उपयोग वर्तमान आवेदक द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ के परिवहन के लिए किया जा रहा था या उपयोग करने की अनुमति दी जा रही थी, जिस पर वाहन का मालिक होने का आरोप है।

6. विद्वान लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि आवेदक के विद्वान वकील द्वारा दिया गया यह तर्क कि उसे धोखा दिया गया है और गलत तरीके से वाहन का पंजीकृत मालिक बना दिया गया है, शायद ही कोई प्रासंगिकता है। उन्होंने कहा कि ऐसी याचिका पर केवल सुनवाई के समय ही विचार किया जा सकता है, इस स्तर पर नहीं।

7. हालाँकि, विद्वान लोक अभियोजक और जाँच अधिकारी न्यायालय को संतुष्ट करने की स्थिति में नहीं थे कि यह कैसे और किस साक्ष्य या सामग्री के आधार पर कहा जा सकता है कि आवेदक ने जानबूझकर आपत्तिजनक वाहन को अपराध के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी है और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 25 के आदेश को पूरा किया गया है।

8. पक्षों के विद्वान वकील को सुना और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

9. जहां तक आवेदक के विद्वान वकील द्वारा दिए गए पहले तर्क का संबंध है कि आवेदक को किसी लाडू राम द्वारा कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए बहकाया गया है, जिसके आधार पर आवेदक को प्रश्नगत वाहन के मालिक के रूप में पंजीकृत किया गया है, परीक्षण के दौरान भी यही तर्क विचारणीय है। यह आवेदक के बचाव का आधार हो सकता है जिसे सीआरपीसी की धारा 313 के तहत उसके बयान की रिकॉर्डिंग के समय

उठाया जा सकता है। लेकिन जमानत आवेदन पर विचार करने के चरण में, उस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

10. इस स्तर पर, भले ही आवेदक को वाहन का पंजीकृत मालिक माना जाता है, अदालत इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकती है कि जांच अधिकारी ने रिकॉर्ड पर कोई जुड़ा हुआ सबूत नहीं लाया है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि वाहन का पंजीकृत मालिक होने के नाते आवेदक ने स्वयं अपने वाहन में प्रतिबंधित पदार्थ का परिवहन किया था या जानबूझकर परिवहन की अनुमति दी थी, जिससे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 25 के प्रावधान आकर्षित हुए।

11. इस संबंध में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 25 पर गौर करने की आवश्यकता है, जो इस प्रकार है:-

> "जो कोई भी किसी घर, कमरे, बाड़े, स्थान, स्थान, जानवर या वाहन का मालिक या कब्जाकर्ता होने या नियंत्रण या उपयोग करने के नाते, जानबूझकर इसे इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत दंडनीय अपराध के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कमीशन के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है, उस अपराध के लिए प्रावधानित दंड से दंडित किया जाएगा। "

12. अभिव्यक्ति का उपयोग "जानबूझकर इसके उपयोग की अनुमति देता है" का अर्थ है कि, यदि किसी घर, कमरे या वाहन आदि का उपयोग एनडीपीएस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के कमीशन में किया गया है, मालिक होने के आधार पर, उसके ज्ञान या सहमति के साक्ष्य के अभाव में; व्यक्त, निहित या मौन, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 25 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

13. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1985 के अधिनियम की धारा 25 एक प्रकार का अचूक अपराध है - जहां मकान या वाहन के मालिक, कब्जेदार आदि को ऐसे घर या वाहन के उपयोग के साथ किए गए अपराध के लिए निर्धारित दंड के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस प्रावधान को संसद द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है और यह अभिव्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है "जानबूझकर अपराध के कमीशन के लिए इसका उपयोग करने की अनुमति देता है"। इसलिए, यह जांच अधिकारी

का कर्तव्य है कि वह रिकॉर्ड सामग्री या साक्ष्य लाए जो यह सुझाव दे कि वाहन को 'जानबूझकर' प्रतिबंधित पदार्थ के परिवहन में उपयोग करने की अनुमति दी गई थी।

14. यह न्यायालय एनडीपीएस अधिनियम की धारा 35 के प्रावधान से परिचित और सचेत है, जो एनडीपीएस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में दोषी मानसिक स्थिति के अस्तित्व का अनुमान प्रदान करता है। हालाँकि, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 25 के तहत एक धारणा उत्पन्न होती है या धारणा तभी बनाई जा सकती है जब जांच एजेंसी या अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य या अन्यथा प्रदर्शित करने के अपने दायित्व का निर्वहन कर लिया हो, कि अभियुक्त को इस बात की जानकारी थी कि वाहन, कमरे और स्थान आदि का उपयोग अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए किया जा रहा था या किया जाएगा।

15. (2005) 4 एससीसी 146 में रिपोर्ट किए गए बलविंदर सिंह और अन्य बनाम सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का लाभकारी संदर्भ यहां दिया जा सकता है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलकर्ता की अपील को इस प्रकार देखते हुए अनुमति दी:

> पैरा 3:- वर्तमान अपीलकर्ता को इस आधार पर दोषी पाया गया है कि वह वाहन पी.जे.ए.8677 का पंजीकृत मालिक था। अपीलकर्ता के वकील का तर्क है कि उन्होंने 1982 में केसर सिंह नामक व्यक्ति के साथ मिलकर यह लॉरी खरीदी थी, लेकिन 1986 में उन्होंने वाहन को तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दिया और जांच अधिकारी, पी.डब्ल्यू.13, जिसकी जांच की गई, ने गवाही दी कि अपनी जांच के दौरान उन्हें पता चला कि यद्यपि वर्तमान अपीलकर्ता पंजीकरण संख्या पी.जे.ए.8677 वाले वाहन का मूल मालिक था, लेकिन उसने 1986 में सुच्चा सिंह नामक व्यक्ति को वाहन बेच दिया था। हालाँकि, पंजीकरण उनके नाम पर नहीं बदला गया था। इस अपीलकर्ता को केवल इस कारण से दोषी ठहराया गया था कि वह वाहन P.J.A.8677 का पंजीकृत मालिक था। <u>यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उसने जानबूझकर किसी व्यक्ति को किसी अवैध उद्देश्य के लिए वाहन का उपयोग करने की अनुमति दी। अभियोजन पक्ष द्वारा रची गई साजिश को साबित करने के लिए भी कोई सबूत नहीं है. इसलिए, यह स्पष्ट है कि हालांकि सामान लॉरी से बरामद किया गया था,</u>

लेकिन यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता का वाहन पर कोई नियंत्रण था और न ही उसके पास ये दवाएं थीं। परिणामस्वरूप, हम अपील की अनुमति देते हैं और अपीलकर्ता बलविंदर सिंह को उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी करते हैं।

16. इस न्यायालय के अनुसार, पुलिस एनडीपीएस अधिनियम की धारा 35 पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं कर सकती है और वैधानिक अनुमान के आधार पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 25 के तहत अपराध के लिए वाहन के मालिक को दोषी नहीं ठहरा सकती है। वैधानिक अनुमान को लागू करने के लिए, प्रारंभिक बोझ का निर्वहन करने के लिए ठोस सामग्री या सबूत रिकॉर्ड पर लाना जांच अधिकारी का गंभीर कर्तव्य है - इस अनुमान को सेवा में दबाया नहीं जा सकता है या शून्य में संचालित नहीं किया जा सकता है।

17. एनडीपीएस अधिनियम एक विशेष कानून है, जिसके मूल में आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नशीली दवाओं के खतरे को संतुलित करना है। इस बात पर जोर देते हुए कि एनडीपीएस अधिनियम एक विशेष कानून है जो कठोर दंड और जमानत देने को नियंत्रित करने वाले कठोर नियमों का प्रावधान करता है, राज्य के लिए आरोपी की मानसिक दोषसिद्धि को साबित करने के अपने बोझ का निर्वहन करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है, लेकिन इसे इस तरह से नहीं किया जा सकता है कि आपराधिक न्यायशास्त्र की व्यापक योजना को नजरअंदाज किया जा सके जो मानसिक दोषीता पर टिकी हुई है। खासकर तब जब वाहन के मालिक के दोषी होने की बात आती है, जिसे उसके ड्राइवर या वाहन चलाने वाले व्यक्ति की गुंडागर्दी के लिए दंडित किया जाना है। इससे भी अधिक, जब विचाराधीन वाहन एक परिवहन/लोडिंग वाहन है, न कि कार, जीप आदि जैसे निजी वाहन, तो जांच एजेंसी पर सबूत इकट्ठा करने का दायित्व बढ़ जाता है।

18. मुख्य आरोपी व्यक्तियों ने अपने प्रकटीकरण बयानों में आवेदक-ट्रक के प्रत्यक्ष मालिक के बारे में कोई खुलासा किए बिना, बस इतना कहा कि दो व्यक्तियों ने ट्रक को श्याम लाल को सौंपने के निर्देश के साथ उन्हें ट्रक सौंपा था। न तो हनुमान और पेमाराम (जो प्रतिबंधित पदार्थ के साथ पाए गए थे) और न ही पदार्थ के कंसाइनर/कंसाइनी श्यामलाल के पास कोई सबूत/कॉल डिटेल आदि है।

19. हरभजन सिंह बनाम हरियाणा राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित 25.04.2023 के हालिया फैसले का उल्लेख करना उपयुक्त होगा: आपराधिक अपील संख्या 1480/2011, 2023 एससीसी ऑनलाइन 490 में रिपोर्ट की गई।

> “7. मौजूदा मामले में, अभियोजन पक्ष यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई भी सामग्री पेश करने में विफल रहा है कि विचाराधीन वाहन, यदि किसी अवैध गतिविधि के लिए इस्तेमाल किया गया था, तो अपीलकर्ता की जानकारी और सहमति से इस्तेमाल किया गया था। यहां तक कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 35 के तहत प्रदान की गई धारणा भी इस कारण से उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि अभियोजन पक्ष मूलभूत तथ्यों को साबित करने के लिए प्रारंभिक बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा था। इसके अभाव में, जिम्मेदारी आरोपी पर स्थानांतरित नहीं होगी।
>
> 8. इस मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा भोला सिंह के मामले (सुप्रा) में विचार किया गया था। यह राय दी गई कि जब तक वाहन का उपयोग उसके मालिक की जानकारी और सहमति से नहीं किया जाता है, जो कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 25 की प्रयोज्यता के लिए अनिवार्य है, तब तक इसके तहत दोषसिद्धि को कानूनी रूप से बरकरार नहीं रखा जा सकता है। उसके प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे निकाले गए हैं:
>
> 9.**********
> 10*******
> 11. अपीलकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज अपने बयान में सभी सुझावों से इनकार किया। अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में पूरे साक्ष्य में, अपीलकर्ता के खिलाफ कोई भी ऐसी सामग्री पेश नहीं की गई जिससे बुनियादी तथ्यों को साबित करने के लिए प्रारंभिक बोझ से मुक्ति मिल सके कि अपराध अपीलकर्ता की जानकारी और सहमति से किया गया था। यह एक ऐसा मामला है जिसमें वह वाहन के साथ नहीं था और न ही दुर्घटना के समय उसे मौके से गिरफ्तार किया गया था या जब ट्रक और प्रतिबंधित पदार्थ को हिरासत में लिया गया था। उसे केवल इस आधार पर दोषी ठहराया गया है कि वह ट्रक का पंजीकृत मालिक था। ट्रायल कोर्ट ने वाहन के पंजीकृत मालिक होने के नाते बचाव का पूरा भार अपीलकर्ता पर डाल दिया था। न्यायालय ने माना कि वाहन का चालक

और क्लीनर गरीब होने के कारण मालिक की मिलीभगत के बिना इतनी बड़ी मात्रा में तस्करी का जोखिम नहीं उठाएंगे और अपीलकर्ता को अपना रुख स्पष्ट करना था। ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था।

12. मौजूदा मामले में, अपीलकर्ता को दोषी ठहराते समय निचली अदालतों द्वारा की गई प्राथमिक त्रुटि यह है कि अभियोजन पक्ष द्वारा मूलभूत तथ्यों को साबित किए बिना अपनी बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी उस पर डालने की मांग की गई है। इसलिए, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को कानूनी रूप से कायम नहीं रखा जा सकता।

13. उपरोक्त कारणों से अपील स्वीकार की जाती है। निम्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त किया जाता है। अपीलकर्ता के जमानत बांड खारिज किये जाते हैं।"

20. इस न्यायालय को 2019 (4) आरएलडब्ल्यू 2738 (राजस्थान) में रिपोर्ट किए गए पूरन राम बनाम राजस्थान राज्य के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित एक फैसले की भी याद दिलाई जाती है, जिसमें अदालत ने इस प्रकार देखा है:

वैधानिक प्रावधान की भाषा को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि इस आरोप को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को अदालत को संतुष्ट करने के लिए सबूत पेश करना होगा कि मालिक या उल्लंघन करने वाले वाहन के नियंत्रण वाले व्यक्ति ने अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वाहन का इस्तेमाल किया या जानबूझकर इस्तेमाल करने की अनुमति दी। मात्र यह आरोप कि वाहन के अंदर से प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई थी, इस संबंध में अभियोजन पक्ष को उसके बोझ से मुक्त नहीं कर देगा। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 35 के तहत अनुमान लगाने का सवाल केवल तभी उठेगा जब अभियोजन पक्ष दंड प्रावधान, यानी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 25 द्वारा उस पर डाले गए प्रारंभिक बोझ का निर्वहन करेगा। अभियोजन पक्ष के समस्त साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए यह अदालत इस बात से पूरी तरह संतुष्ट है कि मामले के रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसके द्वारा अदालत को यह विश्वास दिलाया जा सके कि अपीलकर्ता ने जानबूझकर आपत्तिजनक वाहन को प्रतिबंधित पोस्त भूसे के परिवहन के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग करने की अनुमति दी थी। इस प्रकार, बलविंदर सिंह (सुप्रा)

के मामले में विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुपात पूरी तरह से मामले पर लागू होता है और उपरोक्त अपराध के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज की गई अपीलकर्ता की सजा को कायम नहीं रखा जा सकता है।

21. ऊपर जो देखा गया है उसे ध्यान में रखते हुए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर विचार करते हुए, इस न्यायालय के पास यह विश्वास करने का मजबूत कारण है कि आवेदक न तो जानबूझकर प्रतिबंधित पदार्थ के परिवहन और लेनदेन में शामिल है और न ही उसने जानबूझकर अपराध के लिए वाहन का उपयोग करने की अनुमति दी है। इस प्रकार, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 का अधिदेश संतुष्ट है।

22. परिणामस्वरूप, सीआरपीसी की धारा 439 के तहत दायर जमानत याचिका की अनुमति दी जाती है। आवेदक - बुधाराम पुत्र श्री पेमाराम को पुलिस स्टेशन निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ में दर्ज एफआईआर संख्या 100/2023 के संबंध में गिरफ्तार किया गया, उसे 1,00,000/- रुपये के निजी बांड पर जमानत पर रिहा किया जाएगा। ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये की दो जमानतें।

23. आवेदक को सुनवाई की सभी तारीखों पर और जब भी ऐसा करने के लिए बुलाया जाएगा, उस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा।

24. यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इस न्यायालय द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणियाँ न्यायालय के समक्ष अब तक प्रस्तुत की गई सामग्री के आधार पर हैं। ये केवल प्रथम-दृष्टया टिप्पणियाँ हैं और ये मामले का अंतिम निर्णय करते समय, नेत्र और मौखिक साक्ष्य के आधार पर मामले पर स्वतंत्र दृष्टिकोण लेने के लिए ट्रायल कोर्ट के रास्ते में नहीं आएंगे।

(दिनेश मेहता**),** न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।